BSNLEU
P. Abhimanyu
General Secretary

BSNL EMPLOYEES UNION
Central Head Quarters

Ph.: 011-25705385
Fax : 011-25894862

Main Recognised Representative Union.
Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar,
Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi-110008
E-mail : bsnleuchq@gmail.com, Website : www.bsnleu.in

बीएसएनएलईयू/102 (सर्कुलर संख्या 06/2021) **25 नवंबर, 2021**

सेवा में,

सर्किल सचिव,
केंद्रीय पदाधिकारी
और जिला सचिव।

प्रिय साथियों,

24.11. 2021 को एयूएबी और डीओटी के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा।

डीओटी और एयूएबी के बीच 24.11. 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। एयूएबी द्वारा इस बैठक में चर्चा के लिए सात एजेंडा आइटम दिए गए थे। तदनुसार, बीएसएनएल के पुनरुद्धार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई है।

बैठक की अध्यक्षता डीडीजी (पीएम) श्री संजीव गुप्ता ने की, जो दूरसंचार विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग के कुछ अधिकारी, और बीएसएनएल के सीनियर जीएम (एसआर) भी उपस्थित थे। कॉम. पी. अभिमन्यु, जीएस, बीएसएनएलईयू और एयूएबी के अन्य महासचिवों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शुरुआत में, एयूएबी ने कड़ी शिकायत की कि, श्री मनोज सिन्हा, तत्कालीन संचार राज्य मंत्री और सुश्री अरुणा सुंदरराजन, तत्कालीन सचिव, दूरसंचार द्वारा दिसंबर, 2018 में हुई बैठकों में तीसरे वेतन संशोधन के संबंध में दिए गए आश्वासन, वास्तविक मूल वेतन के आधार पर बीएसएनएल द्वारा पेंशन अंशदान का भुगतान और वेतन संशोधन से पेंशन संशोधन को अलग करना, दूरसंचार विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया। इसलिए, एयूएबी ने जोर देकर कहा कि इस बैठक के लिए मिनट्स/चर्चा का रिकॉर्ड जारी किया जाना चाहिए और लिए गए निर्णयों को दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

एयूएबी द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में, डीडीजी (पीएम) ने कहा कि, इसके बाद डीओटी और एयूएबी के बीच नियमित बातचीत होगी। इसके बाद, उन्होंने एयूएबी द्वारा प्रस्तुत एजेंडा मदों पर प्रतिक्रिया दी। डीडीजी (पीएम) द्वारा निम्नलिखित प्रमुख बिंदओं पर प्रतिकिया व्यक्त की गई।

बीएसएनएल द्वारा 4जी लॉन्च करना।
4जी सेवा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के बीटीएस के उन्नयन के मुद्दे को ईटीजी (एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप) और पीएमओ के पास ले जाया गया। लेकिन, इसे मंजूरी नहीं मिली। पीएमओ ने जोर देकर कहा है कि बीएसएनएल के 4जी उपकरणों का "कोर" भारतीय बनाया जाना चाहिए।

टीसीएस बीएसएनएल को 4जी उपकरणों की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। टीसीएस के सीईओ ने 31 दिसंबर, 2021 तक पीओसी (अवधारणा का सबूत) को पूरा करने का आश्वासन दिया है। पीओ (खरीद आदेश) मार्च/अप्रैल, 2022 तक दिए जाएंगे। बीएसएनएल द्वारा 4 जी सेवा की व्यावसायिक लॉन्चिग अगस्त/ सितंबर, 2022 में होगी।

बीएसएनएल की 4जी लॉन्चिंग के लिए कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) 14,000 करोड़ रुपये और 4जी लॉन्चिंग के लिए एमटीएनएल का कैपेक्स 1,000 करोड़ रुपये आता है। यह 15,000 करोड़ रुपये सरकार वहन करेगी। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट नोट भेजा जाएगा।

दूरसंचार विभाग द्वारा बीएसएनएल को 39,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान।

डीडीजी (पीएम) ने जवाब दिया कि,

(क) WIMAX और CDMA स्पेक्ट्रम की वापसी पर ब्याज, जैसा कि बीएसएनएल द्वारा दावा किया जा रहा है, नहीं आ सकता है। तुलनात्मक रूप से सरकार बीएसएनएल की 4जी लॉन्चिंग और रिवाइवल के लिए बड़ी रकम मुहैया कराने जा रही है।

(ख) डीओटी में किसी अन्य अनुभाग द्वारा छुट्टी नकदीकरण राशि की वापसी को डील किया जा रहा है। उनके साथ इस मुद्दे को उठाया जाना है।

(ग) ग्रामीण टेलीफोनी सेवाओं के कारण बीएसएनएल को मुआवजे का भुगतान करने का मामला माननीय संचार मंत्री द्वारा डील जा रहा है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर को निजी हाथों को नहीं सौंपना।

डीडीजी (पीएम) ने कहा कि बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर के मुद्रीकरण के माध्यम से आने वाली राशि केवल बीएसएनएल को जाएगी। लेकिन, एयूएबी ने इसका खंडन किया और कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, यह राशि केवल सरकार के पास जाएगी। इसलिए, यह दृढ़ता से तर्क दिया गया कि, बीएसएनएल के टावरों और ऑप्टिक फाइबर का कोई मुद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में परिकल्पित है।

वास्तविक मूल वेतन के आधार पर बीएसएनएल द्वारा पेंशन अंशदान का भुगतान।

डीडीजी (पीएम) ने कहा कि, इस मुद्दे को डीओटी द्वारा तीन मौकों पर वित्त मंत्रालय में ले जाया गया था। लेकिन, वित्त मंत्रालय ने मांग को स्वीकार नहीं किया।

कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए बीएसएनएल के भूमि मुद्रीकरण में तेजी लाना।

इस पर, डीडीजी (पीएम) ने कहा कि, वर्तमान में, बीएसएनएल की चार संपत्तियां दीपम के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये में बेची जा रही हैं। यह पैसा बीएसएनएल के पास ही आएगा। उन्होंने आगे कहा कि, सरकार के निर्णय के अनुसार, 10 करोड़ रुपये से कम की भूमि बीएसएनएल द्वारा ही बेची जा सकती है। डीओटी की मंजूरी से 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच की भूमि बेची जा सकती हैं। 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि दीपम के माध्यम से ही बेची जा सकती है।

बीएसएनएल के एक्जीक्यूटिवों और नॉन–एक्जीक्यूटिवों के लिए तीसरे वेतन संशोधन का तत्काल निपटान।

डीडीजी (पीएम) ने कहा कि, इस पर निर्णय केवल माननीय संचार मंत्री द्वारा लिया जा सकता है।

ई 2 और ई 3 मानक वेतनमानों के लिए संशोधित पीओ।

डीडीजी (पीएम) ने कहा कि, इस मुद्दे पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद चर्चा की जा सकती है।

सधन्यवाद,

आपका

(पी. अभिमन्यु)
महासचिव